



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07102020-222278
CG-MH-E-07102020-222278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]
No. 408]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2020/ आश्विन 14, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ASVINA 14, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/90/2016-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, संलग्न आदेशानुसार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामल संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी

परादीप पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश**(सितम्बर 2020 के 8 वें दिन पारित)**

यह मामला परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 पीपीटी के मौजूदा दरमानों का पिछला अनुमोदन इस प्राधिकरण द्वारा **15 सितंबर, 2017** के आदेश संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र में **1 नवंबर, 2017** के राजपत्र संख्या **422** में अधिसूचित किया गया था। आदेश में दरमानों की वैधता **31 मार्च 2019** निर्धारित की गई थी।

2.2 तत्पश्चात, जब पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने दिसम्बर, **2018** में सभी महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण के लिये प्रशुल्क नीति **2018** जारी की तब पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता **30 सितंबर, 2019** तक बढ़ा दी गई थी ताकि वैधता पीपीटी प्रशुल्क नीति **2018** में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के अनुरूप अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर सके।

3.1. इसी पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने अपने **27/30 जुलाई 2019** और बाद में **20 अगस्त, 2019** के पत्र के द्वारा अपने मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार **1 अक्टूबर 2019** से, **1 वर्ष** के लिए करने का अनुरोध इस आधार पर किया कि प्रशुल्क नीति **2018** के खंड **2.5** के अनुसार वर्ष **2018-19** पर आधारित आकलन चालू होने वाली नई/आने वाली परियोजनाओं के कारण कार्गो के पीपीटी परिचालित बर्थों से पीपीपी बर्थों पर अंतरण होने की प्रत्याशा की वजह से **2021-22** तक के प्रशुल्क चक्र के लिये लागू पीपीटी के दरमानों के संशोधन के मानदंड नहीं हैं।

3.2. चूंकि पीपीटी के मौजूदा दरमानों की विस्तारित वैधता **30 सितंबर, 2020** को समाप्त हो रही है, और पीपीटी द्वारा दिये गये कारणों के आधार पर और पीपीटी के दरमानों में निर्वात से बचने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा यह उपयुक्त समझा गया कि पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार **30 सितंबर, 2019** से आगे कर दिया जाए। तदनुसार, इस प्राधिकरण ने **10 अक्टूबर, 2019** के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी द्वारा पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार एक वर्ष की अवधि के लिये कर दिया यानी **01 अक्टूबर 2019** से **30 सितम्बर 2020** तक। उसी आदेश के द्वारा पीपीटी को प्रशुल्क नीति **2018** के अनुपालन में अपना प्रस्ताव **30 जून, 2020** तक दायर करने की सलाह भी दी गयी थी।

4.1. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने **29 जून, 2020** के अपने पत्र संख्या एफए/आरई/123/2019 के द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह निवेदन किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण पीपीटी में निर्माणाधीन पीपीपी परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है और कि व्यापार की वास्तविक मात्रा का आकलन करने में कठिनाई आ रही है, इसलिये पीपीटी ने, **30 जून 2020** तक दरमानों के संशोधित प्रस्ताव को दायर करने पर जोर डाले बिना, मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार **01 अक्टूबर 2020** से और एक वर्ष की अवधि के लिये करने का अनुरोध किया है।

4.2. इस संबंध में, यह कहना होगा के **01 अक्टूबर, 2019** से एक वर्ष की अवधि के लिये मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार चाहते समय बताये गये कारण कि कार्गो की पीपीपी बर्थों को संभावित अंतरण, जो निकट भविष्य में आरम्भ होना था, जिसकी वजह से **2018-19** का यातायात पीपीटी द्वारा एक उपयुक्त मानदंड नहीं समझा गया था। अब पत्तन ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण पीपीटी में निर्माणाधीन पीपीपी अंतर्गत परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है। इसलिये, वर्ष **2020-21** से **2022-23** के प्रशुल्क चक्र के लिये वर्ष **2018-19** के वास्तविक यातायात के आधार पर राजस्व काफी कठिन हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के कारण, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, **1963 (1963 का 38)** की धारा **111** के अंतर्गत **21 अप्रैल, 2020** के पत्र संख्या पीडी-14033/4/2020-पीडी के अंतर्गत महापत्तनों में परिवर्तनों में छूट/परिहार से संबंधित मुद्दों और आपदा से संबंधित मुद्दों से निपटने के निदेश जारी किये हैं और अन्य बातों के साथ साथ पीपीटी सहित

सभी महापत्तनों को निदेश दिया है कि पीपीपी मोड में कार्यान्वयन के अंतर्गत अथवा अन्यथा किसी परियोजना के समापन की अवधि में विस्तार कर दिया जाये।

4.3 पीपीटी द्वारा वयक्त की गयी कठिनाई को देखते हुए तथा ऊपर दिये गये कारणों से और सामुहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता को 01 अक्तूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक की एक वर्ष की अवधि के लिये विस्तार करने को प्रवृत्त है, जैसा पीपीटी ने प्रस्ताव किया है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./269/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2020

No. TAMP/90/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/90/2016-PPT

Paradip Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 8th day of September 2020)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the Paradip Port Trust (PPT).

2.1. The existing SOR of PPT was approved by this Authority vide Order No. TAMP/90/2016-PPT dated 15 September 2017. This Order was notified in the Gazette of India on 1 November 2017 vide Gazette No. 422. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019.

2.2. Thereafter, when the Ministry of Shipping (MOS) in December 2018 issued Tariff Policy, 2018 for fixation of tariff of all Major port Trusts, the validity of the existing SOR of PPT was extended till 30 September 2019, in order to enable PPT formulate its general revision proposal based on stipulations contained in Tariff Policy, 2018.

3.1. Subsequently, the PPT vide its letters dated 27/30 July 2019 and subsequent letter dated 20 August 2019 had requested to extend the validity of the present SOR for a further period of one year w.e.f. 1 October 2019 on the ground that the estimation based on the year 2018-19 as per the clause 2.5 of the Tariff Policy, 2018 is not the yardstick for revision of Scale of rates of PPT applicable for the tariff cycle upto 2021-22 due to anticipated shift of cargo from Port operated berth to PPP berths due to newly commissioned/ upcoming projects.

3.2. Since the extended validity of the existing SOR of PPT was expiring on 30 September 2019 and based on the reasoning given by PPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of PPT, this Authority felt it appropriate to extend the validity of the existing SOR of PPT beyond 30 September 2019. Accordingly, this Authority vide its Order no. TAMP/90/2016-PPT dated 10 October 2019 extended the validity of the existing SOR of PPT for a period of one year i.e. from 1 October 2019 to 30 September 2020. Vide the said Order, the PPT was also advised to file its proposal latest by 30 June 2020, following Tariff Policy, 2018.

4.1. In this backdrop, the PPT vide its letter no. FA/RE/123/2019 dated 29 June 2020 has, interalia, submitted that due to the COVID-19 pandemic, the PPP projects under construction at PPT are getting delayed and that it is very difficult to assess the actual reversal of the business volume, the PPT has requested to extend the validity of the present SOR for a further period of one year w.e.f. 01 October 2020 without insisting for revision proposal of SOR within 30 June 2020.

4.2. In this regard, it is to state that the reason cited by PPT earlier while seeking extension of validity of SOR for a period of one year from 01 October 2019 was the probable shift of cargo to PPP berths, which were to be commissioned in the near future, due to which the traffic of 2018-19 was not felt appropriate by PPT to be considered as yard stick. Now, the Port has stated that due to COVID-19 Pandemic, the PPP Projects under construction at PPT are getting delayed. Hence, estimating the revenue based on the actual of traffic of 2018-19 for the tariff cycle 2020-21 to 2022-23 may not be realistic and it is difficult to assess the reversal of business volumes. It is noteworthy that recognising the situation arising because of COVID-19 pandemic, the Ministry of Shipping in the Government of India vide its directive issued under section-111 of the Major Port Trusts Act, 1963 by letter No. PD-14033/4/2020-PD VII dated 21 April 2020 to deal with the issues at Major Ports relating to exemption/ remission of charges and Force Majeure has inter-alia, directed all the Major Ports including PPT to extend the period of completion of any project under implementation in PPP mode or otherwise.

4.3. In view of the difficulty expressed by the PPT and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority is inclined to extend the validity of the existing SOR of PPT for a period of one year from 01 October 2020 upto 30 September 2021, as requested by the PPT.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./269/2020-21]